एमएसएमई विलंबित भुगतानों के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली समाधान-केंद्रित रिपोर्ट

राष्ट्रीय, 03.03.2023: ग्लोबल अलायंस फॉर मास आंत्रप्रेन्योरशिप (गेम) और कोलैबरेटिव कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन (सी2एफओ / C2FO) द्वारा आज विलंबित भुगतान रिपोर्ट 2.0 जारी की गई। 'एमएसएमई के लिए कार्यशील पूँजी को अनलॉक करने हेतु कल्पनाशील समाधान' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट को भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, डॉ. वी अनंत नागेश्वरन ने जारी किया।

नई लॉन्च की गई यह रिपोर्ट प्रशंसनीय समाधानों को संबोधित करने के साथ ही तीन केंद्रीय स्तंभों पर आधारित है, जिसमें सरकार और नीति निर्माता, वित्त समर्थक और वित्तदाता; भारतीय एमएसएमई के वित्तीय संकट को हल करने के लिए बड़े उद्यम (पीएसयू सहित); और साथ ही वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 10 करोड़ नौकरियों के सृजन पर ध्यान शामिल हैं।

रिपोर्ट का सह-लेखन सी2एफओ और गेम द्वारा किया गया है, जिस पर एमएसएमई (MSME) मंत्रालय के श्री बी बी स्वैन और श्री अजीत सिंह; श्री शरद शर्मा, सह-संस्थापक, आईस्पिरिट (iSPIRIT); श्री विवेक मल्होत्रा, मुख्य महाप्रबंधक, सिडबी (SIDBI); श्री अनिल भारद्वाज, महासचिव, एफआईएसएमई (FISME); श्री आदर्श कुमार, फूड एंड एग्रीकल्चर ग्लोबल प्रैक्टिस, विश्व बैंक (World Bank) के वरिष्ठ कृषि व्यवसाय विशेषज्ञ; और श्री राजेश कुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ट्रांसयूनियन सीआईबीआईएल (CIBIL) द्वारा व्यापक चर्चा की गई।

भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा, *"ग्लोबल एलायंस फॉर मास आंत्रप्रेन्योरशिप ने विलंबित भुगतान जरूरतों के समाधान को गहनता से लेना जारी रखा है, इस तथ्य से मैं काफी खुश हूँ। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसका समय के साथ निरंतर डटकर निपटान किया जा सकता है। इस मुद्दे को न सिर्फ भारत में, बल्कि दुनिया भर के कई देशों में सुलझाया जाना बाकी है। भारत में, एमएसएमई पर सरकार वर्ष 2014 से ध्यान केंद्रित कर रही है। उम्मीद है कि समय के साथ, कुछ विधान-संबंधी और बजटीय घोषणाओं के माध्यम से, न सिर्फ निजी क्षेत्र में, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी मानसिकता में बदलाव लाए जा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, सामान्य बड़े उद्यम व्यवहार के तौर पर, शीघ्र भुगतान संस्कृति के साथ क्रियाविधि और कृत्रिम हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। 2023-24 के बजट में, सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान का दावा एक्रुअल के आधार पर नहीं किया जा सकता है। साथ ही भुगतान नहीं होने की स्थिति तक कर योग्य आय के विपरीत इसका समायोजन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यह कंपनियों के भीतर पारदर्शिता को स्पष्ट करता है। एक जीवंत एमएसएमई क्षेत्र के बिना, हम भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कल्पना नहीं कर सकते हैं।"*

रवि वेंकटेशन, संस्थापक, ग्लोबल अलायंस फॉर मास आंत्रप्रेन्योरशिप (गेम), ने कहा, *"अधिकांश एमएसएमई में वित्तीय सहायता और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सलाह देने वाले समर्थन की कमी पाई जाती है, साथ ही ये तकनीकी क्षेत्र में भी कुछ पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी की बेहतर पहुँच और प्रतिस्पर्धी रणनीति के माध्यम से उद्यम न सिर्फ कुशल बन सकते हैं, बल्कि अधिक रोजगार का सृजन भी कर सकते हैं। निर्बाध नकदी प्रवाह की आवश्यकता भी काफी समय से है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ जीएएमई का विलंबित भुगतान 2.0 एमएसएमई को सफल बनाने के लिए चार-बिंदु समाधान प्रस्तावित करता है।"*

अलेक्जेंडर केम्पर, संस्थापक और सीईओ, सी2एफओ (**Alexander Kemper, Founder & CEO, C2FO**), ने कहा, *"भुगतान में देरी और औपचारिक वित्तपोषण की कमी, देश में नौकरी के सृजन की क्षमता को*

बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। व्यवसाय के मालिकों को भी भुगतान में देरी से निपटान के लिए संघर्ष करते हुए देखा जाता है। लंबे समय तक चलने वाले क्रेडिट मूल्यांकन मानदंडों और प्रक्रियाओं के दबाव के चलते ऋणों तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से, हमने भारत स्टैक (खाता एग्रीगेटर, जीएसटी) का लाभ लेने, क्रेडिट ग्यारंटी योजनाओं को सरल बनाने और इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए खरीदारों और विक्रेताओं के लिए सटीक प्रोत्साहन वाले समाधान जुटाए हैं।"

यह रिपोर्ट इस तरह कार्य करती है, जो लाखों व्यवसायों के औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा न होने के प्रमाण को दर्शाती है, जिससे कभी-भी क्रेडिट तक पहुँच नहीं होती है। देश की नौकरियों के सृजन की क्षमता पर विलंबित भुगतानों और औपचारिक वित्तपोषण की कमी ने प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके परिणामस्वरूप, कहीं न कहीं व्यवसाय के संचालन में बाधाएँ देखने में आती हैं। भुगतान में देरी की समस्या से ग्रसित, व्यवसाय के मालिकों पर गैर-प्रतिनिधि और विशेष मूल्यांकन मानदंड का भी दबाव होता है, जो ऋण तक उनकी पहुँच को सीमित करने के सबसे बड़े कारणों में से एक हैं।

योजनाओं और मानदंडों को पेश करने के सरकार के प्रयासों से ऋण प्रवाह के प्रोत्साहन की उम्मीद है। इसके साथ ही क्रेडिट ग्यारंटी का सरलीकरण करके कैश फ्लो-आधारित उधार व जीएसटी (GST) डेटा को एकीकृत करके टीआरईडीएस (TReDS) को प्रबल बनाया जाएगा और विलंबित भुगतानों के लिए विवाद समाधान की प्रक्रिया की पुनःकल्पना की जाएगी।

पूरी रिपोर्ट को इस लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है: https://massentrepreneurship.org/wp-content/uploads/2023/03/Delayed-Payments-Report-2.0.pdf

ABOUT GLOBAL ALLIANCE FOR MASS ENTREPRENEURSHIP: GAME's mission is to catalyze an India-wide entrepreneurial movement and favourable conditions for the growth of existing and new enterprises resulting in 50 million new jobs by 2030. We aim to ensure that a significant percentage of new businesses are women-owned. We hope to inspire and support similar movements in other parts of the world facing similar challenges. GAME is a non-profit operating as a project under Junior Achievement India Services. For more information, visit: https://massentrepreneurship.org/

ABOUT C2FO: C2FO is the world's on-demand working capital platform, providing fast, flexible, and equitable access to low-cost capital to nearly 2 million businesses worldwide. Using patented Name Your Rate® technology and a suite of working capital solutions, companies can get paid sooner by the world's largest enterprises— unlocking billions in risk-free capital. With a mission to ensure that every business has the capital needed to thrive, C2FO has delivered more than $225 billion in funding worldwide. Founded in 2008 and headquartered in Kansas City, USA, with offices around the globe, C2FO is working to build a better, more inclusive financial system every day. To learn more, visit C2FO.com.

MEDIA CONTACTS:

Archana Parthasarathy || One Source || +91 99209 40003 || archana.parthasarathy@one-source.co.in
Naeem Shaikh || One Source || +91 90227 41986 || naeem.shaikh@one-source.co.in